

बरोनी और कटिहार के बीच की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4282. श्री सीताराम केसरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरोनी और कटिहार के बीच की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हा, तो इस योजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री जे० मु० पुनावा) :

(क) जी नहीं।

(ख) गवाल नहीं उठना।

सूडान को मसालों का निर्यात

4283. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री अर्जुन सिंह भबौरिया :
श्री श्री० प्र० त्यागी :
श्री आलम दास :
श्री हुकम चन्द कक्काव : '

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूडान में भारतीय मसालों की बहुत मांग है,

(ख) क्या सरकार अन्य देशों में भारतीय मसालों की खपत बढ़ाने के लिये कोई योजना बना रही है; और

(ग) वर्ष 1966-67 के दौरान विभिन्न देशों को निर्यात किये गये मसालों की मात्रा तथा इससे कमायी गयी विदेशी मुद्रा राशि कितनी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री विवेक सिंह) :

(क) तथा (ख). जी, हाँ।

(ग) वर्ष 1966-67 में विभिन्न देशों को 26.2 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 48,000 मेट्रिक टन मसालों का निर्यात किया गया।

आयात किये गये ट्रैक्टरों का मूल्य

4284. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामाबतार शर्मा :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री० सुर्व प्रकाश पुरी :
श्री हुकम चन्द कक्काव :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री आलम दास :
श्री अर्जुन सिंह भबौरिया :
श्री श्री० प्र० त्यागी :

क्या औद्योगिक विकास तथा सज्जाव-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात किये हुए ट्रैक्टरों की कीमत देश में ही बनाये गये ट्रैक्टरों की कीमत से कम है.

(ख) क्या हमका कारण यह है कि आयात किये जाने वाले ट्रैक्टरों पर शुल्क कम लगता है; और

(ग) यदि हा, तो क्या सरकार भाग्यीय ट्रैक्टर निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिये मं एक योजना बना रही है ?

औद्योगिक विकास तथा सज्जाव-कार्य मंत्री

(श्री कलचहीन शर्मा अहमद) : (क) जी, हाँ।

(ख) कृषि के काम धाने वाले ट्रैक्टर सीमा शुल्क से मुक्त हैं किन्तु देशी ट्रैक्टरों की कीमत कई कारणों से अपेक्षाकृत अधिक है। जैसे आयातित और देशी करीबे गये पुर्जों की कीमत अधिक होती है, कच्चे माल की ऊँची कीमत है तथा कुछ ऐसे पुर्जों पर सीमा शुल्क देना पड़ता है जो कृषि ट्रैक्टरों के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में भी इस्तेमाल किये जाते हैं।